**जुलाई, 2008 माह के दौरान शहरी विकास मंत्रालय के संबंध में मंत्रिपरिषद्, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सचिवों आदि के मध्य परिचालित करने हेतु महत्वपूर्ण कार्यो का मासिक सार**

********

शहरी विकास मंत्रालय के संबंध में जुलाई, 2008 के दौरान किए गए महत्वपूर्ण नीति निर्णयों/कार्यो का मासिक सार निम्नलिखित हैः-

1. **सार्वजनिक महत्व के कार्य**

(i) माह के दौरान के0 लो0 नि0 वि0 द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए गए ।

(क) सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत उप-राज्यपाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ने 15.7.2008 को लिटिल अंडमान द्वीप समूह में लाभार्थियों को 216 मकानों की चाबी दी है ।

2. **महत्वपूर्ण नीति संबंधी मुद्दे**

(i) विश्व बैंक- वैश्विक पर्यावरणीय सुविधाएं (जीईएफ)- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम(यूएनडीपी) से सहायता प्राप्त सुस्थिर शहरी परिवहन परियोजना की स्थिति की समीक्षा करने के लिए सचिव (शहरी विकास ) की अध्यक्षता में 3.7.2008 को संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई थी ।

(ii) नेशनल फेसीलिटेशन कमेटी की 12 जून, 2008 को आयोजित छठीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, मेट्रो एयरपोर्टो अर्थात कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद और बंगलौर को विशेष रुप से आपस में जोड़ने संबंधी मुद्दे को देखने के लिए यह मंत्रालय एक बैठक आयोजित कर सकता है । तदनुसार कोलकाता, बंगलौर, दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद एयरपोर्ट को एक्सप्रेस रेल/सड़क से जोड़ने के संबंध में सचिव(शहरी विकास ) की अध्यक्षता में निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार बैठकें आयोजित की गईः-

| शहर | बैठक की तारीख |
|---|---|
| 1. कोलकाता और बंगलौर | 8.7.2008 |
| 2. दिल्ली | 15.7.2008 |
| 3. चेन्नई और हैदराबाद | 28.7.2008 |

(iii) **डेवलपिंग इंडियाज म्यूनिसिपल बांड मार्किटः कन्सट्रेन्टस टू ओवरकम पर वर्किंग सेशन**

डेवलपिंग इंडियाज म्यूनिसिपल बांड मार्किटः कन्सट्रेन्टस टू ओवरकम पर वर्किंग सेशन मेरी अध्यक्षता में वित्त मंत्रालय के साथ संयुक्त रुप से शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 29 जुलाई, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था । राज्य सरकार, आर बी

आई, एल आई सी, निजी क्षेत्र/संस्थागत निवेशकों और अन्तर्राष्ट्रीय विकास पार्टनरों के प्रतिनिधियों ने सेशन में भाग लिया। निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गईः

1. ब्याज दर पर नियंत्रण।
2. म्युनिसिपल बाण्डों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र की स्थिति।
3. सामाजिक अवसंरचना ऋण/बीमा कंपनियों के लिए अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के अंतर्गत मान्यता।
4. धारा 14(क) में सीमित संशोधन
5. उच्च क्रेडिट रेटिंग इन्हेंसमेंट फंड (सीआरईएफ) साझा वित्त विकास कोष(पीएफडीएफ) स्कीम के अंतर्गत करयोग्य बांड
6. सीआरईएफ पर अर्जित ब्याज-कर छूट
7. अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाना

(iv) **जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत किए गए कार्यों की विशेषताएं:-**

(क) दिनांक 18.7.2008 को केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति(सीएसएमसी) की बैठक आयोजित की गई।

(ख) वित्त मंत्रालय द्वारा एक परियोजना के लिए 386.85 लाख रु0 की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) जारी की गई।

(ग) वित्त मंत्रालय द्वारा दो समुदाय सहभागिता सुविधा (सीपीएफ) परियोजनाओं के लिए - 18.52 लाख रु0 जारी किए गए।

(घ) शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्त पोषण पर विचार करने और तौर-तरीके सुझाने हेतु योजना आयोग द्वारा गठित समूह की सचिव(यूडी) की अध्यक्षता में दिनांक 8.7.2008 को पहली बैठक आयोजित की गई।

(ड.) स्वच्छ पानी के स्रोतों पर दबाव कम करने के लिए पेयजल आपूर्ति बढ़ाने हेतु गंदे पानी का पुनर्शोधन/पुनः उपयोग करने संबंधी मामले पर विचार करने के लिए सचिव (यूडी)की अध्यक्षता में दिनांक 28.7.2008 को बैठक आयोजित की गई।

(च) हाल ही में आरंभ ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं को शुरु करने तथा कार्यान्वित करने में तेजी लाने संबंधी मामले पर चर्चा करने हेतु राज्य और शहर स्तरीय प्रतिनिधियों की सहभागिता से सचिव (यूडी) की अध्यक्षता में दिनांक 30.7.2008 को बैठक आयोजित की गई।

(छ) जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत नगर विकास योजना (सीडीपी), करार ज्ञापन (एमओए) एवं केन्द्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) की बैठक के संबंध में प्रगति रिपोर्ट अनुलग्नक-I में है।

(V) **छोटे एवं मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के अंतर्गत कार्रवाई की किए गए कार्यों की मुख्य विशेषताएं:-**

(क) यूआईडीएसएसएमटी की केन्द्रीय सहायता प्राप्त स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2008-09 हेतु 879.69 करोड़ रु0 का परिव्यय निर्धारित किया गया है ।

जुलाई, 2008 के दौरान 26 कस्बों में 26 परियोजनाओं के लिए (18 जल आपूर्ति परियोजनाएं-गुजरात के 9 कस्बों में 9, कर्नाटक के 4 कस्बों में 4 तथा उत्तर प्रदेश के 5 कस्बों में 5, 3 सीवरेज परियोजनाएं- राजस्थान के 2 कस्बों में 2 तथा कर्नाटक में एक, 4 कचरा प्रबंधन परियोजनाएं- उत्तर प्रदेश के 4 कस्बों में 4, तथा 1 सड़क परियोजना-उत्तर प्रदेश के 1 कस्बे में 1) 149.00 करोड़ रु0 की एसीए की प्रथम किस्त जारी की गई है ।

संचयी आधार पर 31.7.2008 तक 373 कस्बों में 457 परियोजनाओं के लिए 2692.82 करोड़ रु0 एसीए की प्रथम किस्त तथा 3 राज्यों के 9 कस्बों में 9 परियोजनाओं हेतु 17.54 करोड़ रु0 की दूसरी किस्त जारी की गई है, अर्थात 373 कस्बों में 457 परियोजनाओं हेतु कुल 2710.36 करोड़ रु0 जारी किए गए हैं ।

(ख) शहरी विकास मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में 3 जल आपूर्ति परियोजनाओं तथा आंध्र प्रदेश में 10 जल आपूर्ति, 4 बरसाती नालों, 2 सड़कों तथा 1 सीवरेज परियोजना के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता रिलीज करने हेतु वित्त मंत्रालय से सिफारिश की है ।

(ग) जून, 2008 को समाप्त तिमाही तक की तिमाही प्रगति रिपोर्टें मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा से प्राप्त हो गई हैं ।

(घ) गुजरात से 12 संशोधित उपयोग प्रमाणपत्र तथा मध्य प्रदेश से 1 कुल 13 उपयोग प्रमाणपत्र हुए हैं ।

(vi) नेताजी नगर के पुनर्विकास हेतु परियोजना(नई दिल्ली में सरकारी आवास योजना) के अंतर्गत की गई प्रगति:-

(क) एनबीसीसी को टाईप-vi मकानों, यदि ये केलोनिवि द्वारा परीक्षित प्राक्कलनों में आते हैं, तो इनके लिए निविदा प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी गई ताकि विलंब के कारण लागत में वृद्धि न हो ।

(ख) एनबीसीसी को निदेश दिया गया है कि नीलाम किए गए भूखंड के समीप एक एकड़ व्यवसायिक भूमि की सुरक्षा व संरक्षण हेतु की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट दी जाए ।

(ग) रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से सफदरजंग रेलवे स्टेशन के सामने अफ्रीका एवेन्यू से शांति पथ तक सड़क जोड़ने के लिए रेलवे भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है ।

(घ) एनबीसीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने बताया है कि प्राप्त विभिन्न सुझावों के अनुसार टाईप-vii मकानों का डिजाइन संशोधित किया गया है ।

(ड.) एनबीसीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने बताया है कि प्लाट में आने वाली नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और केलोनिवि की पाइपलाइनों को स्थानांतरित करने, परियोजना के भू-दृश्य निर्माण और क्वालिटी जांच पर होने वाला खर्च आकस्मिक प्रभारों से किया जाएगा ।

(vii) मैसूर, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर स्थित तीन भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालयों के निजीकरण के संबंध में मंत्रिमंडल निर्णय के कार्यान्वयन की अनुपालन रिपोर्ट/ सामने आ रही कठिनाईयों से संबंधित स्थिति अनुलग्नक-।। में दी गई है ।

(viii) नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लि0 को जुलाई, 2008 के दौरान सौंपे गए कार्यों के विवरण अनुलग्नक-।।। में दिए गए हैं ।

(ix) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के हित की परियोजनाओं / योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान के अंतर्गत जुलाई, 2008 के दौरान दी गई धनराशि का विवरण अनुलग्नक-iV में दिया गया है ।

(x) जुलाई, 2008 के अंत तक दिल्ली में संपदा निदेशालय द्वारा आवंटित / पेशकश किए गए / खाली कराए गए सरकारी मकानों की संख्या और बेदखली मामलों की संख्या से संबंधित विवरण अनुलग्नक-V में दिया गया है ।

**अनुलग्नक-I**

## जुलाई, 2008 के दौरान जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम ) के तहत प्रगति

| मद | जून, 2008 तक की स्थिति | जुलाई, 2008 तक की स्थिति | अद्यतन स्थिति |
|---|---|---|---|
| **शहरी विकास योजना(सीडीपी)** | | | |
| **i . प्राप्त** | 63 | -- | जेएनएनयूआरएम के तहत सभी 63 शहरों के लिए मूल्यांकित सीडीपी |
| **ii . मूल्यांकित** | 63 | -- | |
| **करार ज्ञापन (एमओए)** | | | |
| **i . हस्ताक्षरित** | 62 | - | 62 |
| **केन्द्रीय संस्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) बैठके** | | | |
| **i .आयोजित बैठकों की संख्या** | 54* | 1* | 55* |
| **ii . अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या** | 330 | 3 | 333 |
| **iii.वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एसीए** | 4183.83 करोड़ रू0 | 24.06 करोड़ रू0 | 4183.83 करोड़ रू0 |

* दो विशेष सीएसएमसी बैठकों को मिलाकर, जो कि 04.06.07 और 13.06.07 को आयोजित की गई ।

**अनुलग्नक-।।**

**मैसूर, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर स्थित भारत सरकार के तीन पाठ्यपुस्क मुद्रणालयों के निजीकरण से संबंधित मंत्रिमंडल के निर्णय के कार्यान्वयन में महसूस की जा रही कठिनाइयों की स्थिति**

********

मंत्रिमंडल ने दिनांक 1.2.2006 को हुई अपनी बैठक में मैसूर, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर स्थित भारत सरकार के तीन पाठ्यपुस्तक मुद्रणालयों का निजीकरण करने का निर्णय लिया था ।

पाठ्यपुस्तक मुद्रणालयों के निजीकरण से संबंधित मंत्रिमंडल के निर्णय के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए इस मंत्रालय के दिनांक 30 जुलाई, 2008 के अ.शा.पत्र के तहत दिनांक 30.9.2008 तक समय बढ़ाने की मांग की गई है ।

****

**अनुलग्नक-III**

**जुलाई, 2008 के दौरान नेशनल बिल्डिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) को सौंपे गए कार्य**

**( लाख रुपये में)**

| क्र0 सं0 | कार्य का नाम | कायार्थी | कीमत (लाख रुपए) |
|---|---|---|---|
| 1 | आईआईटी, रुड़की में बहुमंजिले "ए" श्रेणी आवासों का निर्माण | आईआईटी, रुड़की | 14.66 |
| 2 | एएचईसी के नजदीक नए बहुमंजिले पुरुष छात्रावासों का निर्माण (आईआईटी, रुड़की में लगभग 670 सीट) | आईआईटी, रुड़की | 25.76 |
| 3 | आईआईटी, रुड़की में लेक्चर हॉल काम्पलेक्स का निर्माण | आईआईटी, रुड़की | 13.47 |

**अनुलग्नक-IV**

**जुलाई, 2008 माह के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में परियोजनाओं के लिए स्वीकृत/जारी की गयी धनराशि**

| क्र0सं0 | परियोजना का नाम | जारी धनराशि (लाख रुपये में) |
|---|---|---|
| 1 | नमची सिक्किम में जिला पुस्तकालय एवं म्यूजियम का निर्माण (एनबीसीसी) | 193.01 |
| 2 | तेलियामुरा में सुपर बाजार का निर्माण (एनबीसीसी) | 111.76 |
| 3 | मौलांग, शिलांग में बस/एलएमवी पार्किंग एवं बाजार का निर्माण (एनबीसीसी) | 337.22 |
| 4 | ऐजवाल, मिजोरम में सड़कों का सुधार (एनबीसीसी) | 715.51 |
| 5 | शिलांग में अंजली सिनेमा के सामने बस/एलएमवी पार्किंग एवं बाजार का निर्माण (एनबीसीसी) | 59.20 |
| 6 | एलांग कस्बा, अरुणाचल प्रदेश में इंडोर स्टेडियम का निर्माण तथा खेल परिसर का सुधार (राज्य सरकार) | 130.85 |
| 7 | चिम्पू, अरुणाचल प्रदेश में खेल परिसर का सुधार (राज्य सरकार) | 136.50 |
| 8 | कुमारघाट, त्रिपुरा में बाजा परिसर का निर्माण (एनबीसीसी) | 361.06 |
| 9 | नमची, सिक्किम में मल्टी लेवल कार पार्किंग एवं शॉपिंग काम्प्लेक्स का निर्माण (एनबीसीसी) | 501.27 |
| 10 | मियाओ, अरुणाचल प्रदेश में इंडोर स्टेडियम का निर्माण तथा खेल परिसर का सुधार (राज्य सरकार) | 120.62 |
| 11 | तम्लू, नागालैण्ड में शॉपिंग काम्प्लेक्स का निर्माण (राज्य सरकार) | 112.88 |

**अनुलग्नक-V**

**जुलाई ,2008 के अंत तक दिल्ली में संपदा निदेशालय द्वारा आवंटित / पेशकश किए गए / खाली कराए गए सरकारी मकानों /क्वार्टरों की संख्या और लंबित बेदखली मामलों की संख्या**

****

| टाईप | आवंटित/ पेशकश किए गए मकानों की संख्या | स्वीकार किए गए मकानों की संख्या | मकानों की संख्या जिन्हें नामंजूर करने के कारण आगे ले जाया गया | रद्द किए गए क्वार्टरों की संख्या जिनमें इस माह के दौरान बेदखली कार्रवाई शुरू की गई है | ऐसे क्वार्टरों की कुल संख्या जिनके संबंध में बेदखली कार्रवाई चल रही है |
|---|---|---|---|---|---|
| टाईप-I | 503 | 196 | 175* | 17 | 51 |
| टाईप-II | 689 | 180 | 509 | 51 | 132 |
| टाईप-III | 580 | 132 | 448 | 35 | 157 |
| टाईप- iv | 125 | 66 | 59 | 09 | 12 |
| टाईप- iv (स्पेशल) | 40 | 12 | 28 | -- | 18 |
| टाईप- V क (डी-II) | 38 | 11 | 27 | 02 | 43 |
| डी-I | 50 | 13 | 37 | 01 | 03 |
| सी-II | 14 | 6 | 08 | -- | -- |
| सी-I व उससे ऊपर | 3 | 1 | 02 | -- | 09 |
| हॉस्टल | 109 | 18 | 91 | 01 | 02 |

* 132 क्वार्टरों के लिए अभी भी आवंटियों से स्वीकृति/अस्वीकृति प्रतीक्षित है ।